

उत्तर प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं का सर्वेक्षण: प्रवृत्ति, कारण और सामाजिक प्रभाव का अध्ययन

अजय कुमार सिंह (शोधार्थी)

विधि विभाग, तिलकधारी सिंह स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, पीली कोढ़ी, जौनपुर

प्रोफेसर (डॉ) संतोष कुमार सिंह

विधि विभाग, तिलकधारी सिंह स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, पीली कोढ़ी, जौनपुर

सार:

उत्तर प्रदेश में वाहन दुर्घटनाएँ एक गंभीर और बढ़ती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्या बन चुकी हैं। राज्य में बढ़ती आबादी, शहरीकरण, मोटर वाहनों की संख्या में तीव्र वृद्धि और परिवहन अवसंरचना की चुनौतियाँ दुर्घटनाओं के उच्च जोखिम के प्रमुख कारण हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति, उनके प्रमुख कारण और उनके सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण करना है। अध्ययन में पिछले दस वर्षों के जिलावार और समय-आधारित आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है, साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को भी उजागर किया गया है। शहरी जिलों में कुल दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है, जबकि ग्रामीण जिलों में मृत्यु-दुर्घटना अनुपात उच्च पाया गया। प्रमुख कारणों में ओवर-स्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाना, हेलमेट और सीट-बेल्ट का उपयोग न करना, सड़क की खराब स्थिति, अपर्याप्त यातायात संकेतक और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की कमी शामिल हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से, वाहन दुर्घटनाओं का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार और समाज पर भी भारी आर्थिक और मानसिक बोझ डालता है। स्थायी विकलांगता, आय में कमी और मानसिक तनाव जैसी चुनौतियाँ प्रभावित परिवारों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। अध्ययन के उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी सड़क सुरक्षा उपाय, बेहतर अवसंरचना, कड़े नियम प्रवर्तन और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में सुधार अनिवार्य हैं। यह शोध नीति निर्माताओं, प्रशासन और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

मुख्य शब्द: वाहन दुर्घटना, उत्तर प्रदेश, मृत्यु-दुर्घटना अनुपात, सड़क सुरक्षा, सामाजिक प्रभाव

प्रस्तावना

सड़क परिवहन आधुनिक समाज की जीवनरेखा है, जो आर्थिक विकास, सामाजिक संपर्क, औद्योगिक गतिविधियों तथा क्षेत्रीय एकीकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसे विकासशील देश में सड़क परिवहन न केवल आवागमन का प्रमुख साधन है, बल्कि यह कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं

को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। किंतु सड़क परिवहन के तीव्र विस्तार के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की समस्या भी गंभीर रूप धारण करती जा रही है। सड़क दुर्घटनाएँ आज केवल एक यातायात संबंधी समस्या नहीं रह गई हैं, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर चुकी हैं। भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहाँ सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और चोटों की संख्या अत्यंत अधिक है। बढ़ती जनसंख्या, तीव्र नगरीकरण, मोटर वाहनों की संख्या में तीव्र वृद्धि, अपर्याप्त सड़क अवसंरचना, यातायात नियमों का कमजोर प्रवर्तन तथा वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की लापरवाह प्रवृत्ति ने सड़क दुर्घटनाओं की समस्या को और जटिल बना दिया है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्रतिवर्ष लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं तथा उससे कहीं अधिक लोग गंभीर या स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं। इसका सीधा प्रभाव न केवल पीड़ित परिवारों पर पड़ता है, बल्कि यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ डालता है।

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य का भौगोलिक विस्तार, विशाल जनसंख्या, ग्रामीण-शहरी मिश्रित संरचना तथा व्यापक सड़क नेटवर्क इसे परिवहन गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बनाता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, जिला सड़कों तथा ग्रामीण संपर्क मार्गों का जाल फैला हुआ है, जो राज्य के भीतर और अन्य राज्यों के साथ संपर्क स्थापित करता है। किंतु इसी व्यापक सड़क नेटवर्क के साथ सड़क दुर्घटनाओं की समस्या भी अत्यधिक गंभीर रूप में विद्यमान है। उत्तर प्रदेश लंबे समय से सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु संख्या के मामले में देश में अग्रणी राज्यों में रहा है। राज्य में प्रतिवर्ष हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं तथा लाखों लोग घायल होते हैं। यह स्थिति न केवल यातायात प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर करती है, बल्कि प्रशासनिक क्षमता, नीति क्रियान्वयन तथा जन-जागरूकता की सीमाओं को भी रेखांकित करती है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण राज्य की कार्यशील जनसंख्या प्रभावित होती है, जिससे उत्पादकता में कमी आती है और गरीबी तथा सामाजिक असुरक्षा की समस्या और गहरी हो जाती है।

उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की प्रकृति बहुआयामी है। शहरी क्षेत्रों में यातायात घनत्व, अतिक्रमण, सार्वजनिक परिवहन की कमी तथा निजी वाहनों की अधिकता दुर्घटनाओं को बढ़ावा देती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में खराब सड़कें, अपर्याप्त संकेतक, प्रकाश व्यवस्था की कमी तथा आपातकालीन सेवाओं की अनुपलब्धता दुर्घटनाओं को अधिक घातक बना देती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों और उच्च गति वाले कॉरिडोर पर ओवर-स्पीडिंग, भारी वाहनों की अधिक आवाजाही तथा यातायात नियमों की अनदेखी के कारण गंभीर दुर्घटनाएँ होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं के पीछे मानवीय कारणों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वाहन चालकों द्वारा ओवर-स्पीडिंग, शराब या नशीले पदार्थों के सेवन के बाद वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग, हेलमेट और सीट-बेल्ट का प्रयोग न करना तथा यातायात नियमों की अवहेलना दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। इसके साथ-साथ सड़क अभियांत्रिकी में कमियाँ, वाहन की तकनीकी खराबियाँ तथा मौसम संबंधी कारक भी दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इन सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव सड़क दुर्घटनाओं को एक जटिल और चुनौतीपूर्ण समस्या बना देता है।

सड़क दुर्घटनाओं का प्रभाव केवल मृत्यु और चोट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। दुर्घटनाओं के कारण परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, विशेषकर तब जब परिवार का कमाने वाला सदस्य दुर्घटना का शिकार हो जाता है। चिकित्सा व्यय, पुनर्वास लागत, कार्य-दिवसों की हानि तथा दीर्घकालिक विकलांगता परिवारों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देती है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सड़क दुर्घटनाएँ स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ाती हैं और विकास संसाधनों को प्रभावित करती

हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की समस्या का वैज्ञानिक, व्यवस्थित एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। केवल आँकड़ों के संकलन से समस्या का समाधान संभव नहीं है, बल्कि दुर्घटनाओं के पैटर्न, कारणों, जोखिम समूहों तथा क्षेत्रीय भिन्नताओं का गहन विश्लेषण आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के सर्वेक्षण और विश्लेषण पर केंद्रित है। इस अध्याय में वर्ष-वार, जिलावार, समय-आधारित, सड़क-प्रकार आधारित तथा वाहन-प्रकार आधारित दुर्घटना आँकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों, पीड़ितों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल तथा सड़क सुरक्षा नीतियों की प्रभावशीलता का भी परीक्षण किया जाएगा। यह अध्याय न केवल वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करता है, बल्कि भविष्य की नीति-निर्माण प्रक्रिया के लिए एक ठोस आधार भी प्रदान करता है। इस अध्ययन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु विभिन्न सरकारी योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सड़क सुरक्षा नीति, ब्लैक-स्पॉट सुधार, ई-चालान प्रणाली तथा iRAD/eDAR जैसी डिजिटल पहलें। किंतु इन पहलों की वास्तविक प्रभावशीलता का मूल्यांकन आवश्यक है, ताकि यह समझा जा सके कि ये उपाय किस हद तक दुर्घटनाओं को कम करने में सफल रहे हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। यह प्रस्तावना अध्याय-6 के शेष भागों के लिए वैचारिक एवं संदर्भात्मक आधार प्रदान करती है। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता, अध्ययन की आवश्यकता तथा शोध के व्यापक सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ स्पष्ट होते हैं। आगामी अनुभागों में प्रस्तुत विश्लेषण न केवल अकादमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि नीति-निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े हितधारकों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।

अध्ययन के उद्देश्य

1. उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना तथा वर्ष-वार दुर्घटना, मृत्यु एवं घायल व्यक्तियों की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना।
2. राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि राज्य का योगदान देश की कुल सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु में कितना है।
3. जिलावार सड़क दुर्घटनाओं के वितरण का विश्लेषण करना तथा उच्च जोखिम (High-Risk) जिलों की पहचान करना।

शोध प्रश्न

1. उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति समय के साथ किस प्रकार परिवर्तित हुई है?
2. राष्ट्रीय स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति की तुलना में उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसी है?
3. लागू सड़क सुरक्षा नीतियाँ एवं कार्यक्रम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में किस हद तक प्रभावी सिद्ध हुए हैं?

इस प्रकार निर्धारित उद्देश्य एवं शोध प्रश्न पूरे अध्ययन को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं तथा आगे के विश्लेषणात्मक अध्यायों के लिए वैचारिक ढाँचा निर्मित करते हैं।

अनुसंधान रूपरेखा

अनुसंधान रूपरेखा किसी भी शोध अध्ययन की आधारशिला होती है, क्योंकि इसी के माध्यम से शोध की दिशा, पद्धति, डेटा के स्रोत, विश्लेषण की तकनीकें तथा अध्ययन की सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं। प्रस्तुत शोध सड़क दुर्घटनाओं जैसी जटिल सामाजिक समस्या का अध्ययन करता है, अतः इसके लिए एक सुविचारित, व्यवस्थित एवं बहुआयामी अनुसंधान रूपरेखा अपनाई गई है। यह अध्ययन वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक दोनों प्रकार की शोध पद्धतियों का संयोजन है, जिससे न केवल तथ्यों का विवरण प्रस्तुत किया जा सके, बल्कि उनके पीछे निहित कारणों और प्रभावों का भी गहन विश्लेषण किया जा सके।

प्रवृत्ति विश्लेषण

प्रवृत्ति विश्लेषण किसी भी सामाजिक समस्या के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके माध्यम से समय के साथ होने वाले परिवर्तनों, वृद्धि या कमी के पैटर्न और समस्या की गंभीरता का मूल्यांकन किया जा सकता है। सड़क दुर्घटनाओं के संदर्भ में, प्रवृत्ति विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि दुर्घटनाओं की संख्या, मृत्यु दर और घायलों की स्थिति किस दिशा में बढ़ या घट रही है। उत्तर प्रदेश जैसे जनसंख्या-बहुल और विशाल राज्य में यह अध्ययन विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि यह राज्य राष्ट्रीय स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामलों में अग्रणी रहा है।

वर्ष-वार सड़क दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति

पिछले एक दशक के आँकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में समग्र रूप से बढ़ती प्रवृत्ति रही है, यद्यपि कुछ वर्षों में मामूली उतार-चढ़ाव भी देखे गए हैं। मोटर वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार और यातायात दबाव में वृद्धि दुर्घटनाओं की बढ़ोतरी के मुख्य कारण हैं। विशेषकर 2015 के बाद वाहन पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसका सीधा प्रभाव दुर्घटनाओं पर पड़ा। कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण दुर्घटनाओं में अस्थायी कमी आई, पर सामान्य आवागमन बहाल होने पर यह संख्या पुनः बढ़ गई।

तालिका 1: उत्तर प्रदेश में वर्ष-वार सड़क दुर्घटनाएँ, मृत्यु एवं घायल (काल्पनिक डेटा)

वर्ष	दुर्घटनाएँ (No.)	मृतक (No.)	घायल (No.)
------	------------------	------------	------------

2014	50,000	7,500	65,000
2015	55,000	8,200	70,000
2016	58,500	8,800	73,500
2017	60,000	9,500	76,000
2018	62,500	10,200	78,500
2019	65,000	11,000	82,000
2020	45,000	7,800	60,000
2021	55,500	9,600	74,000
2022	63,000	11,200	80,500
2023	67,000	12,000	85,000

तालिका में 2020 में कमी कोविड-19 लॉकडाउन के कारण हुई थी।

सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु प्रवृत्ति:-

उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर अधिक तेजी से बढ़ी है, जिससे स्पष्ट होता है कि दुर्घटनाएँ अधिक घातक होती जा रही हैं। इसके मुख्य कारण हैं: ओवर-स्पीडिंग, हेलमेट/सीट-बेल्ट का न उपयोग, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की देरी और दुर्घटना के बाद सहायता की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर चिकित्सा सुविधा न मिलने से मृत्यु की संभावना अधिक है, जबकि शहरी क्षेत्रों में तेज गति और भारी यातायात के कारण गंभीर दुर्घटनाएँ होती हैं।

घायल व्यक्तियों की प्रवृत्ति:-

घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इनमें से कई लोग स्थायी विकलांगता का शिकार हो जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यह दर्शाता है कि सड़क दुर्घटनाएँ केवल आकस्मिक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक समस्या बन चुकी हैं।

राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तर प्रदेश:-

राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक है। कुछ राज्यों में दुर्घटनाओं की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर उच्च होने के कारण यह राज्य सड़क सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाता है।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवृत्ति:-

शहरी क्षेत्रों में दुर्घटनाएँ यातायात घनत्व, निजी वाहनों की अधिकता और सार्वजनिक परिवहन की सीमाओं से जुड़ी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खराब सड़कें, अपर्याप्त संकेतक, प्रकाश व्यवस्था की कमी और आपातकालीन सेवाओं की अनुपलब्धता दुर्घटनाओं को अधिक घातक बनाती हैं।

समय के साथ नीति हस्तक्षेपों का प्रभाव:-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेप किए गए हैं, जैसे ई-चालान प्रणाली, ब्लैक-स्पॉट सुधार, सड़क सुरक्षा सप्ताह और डिजिटल निगरानी। कुछ क्षेत्रों में इन उपायों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन समग्र रूप से दुर्घटनाओं में अपेक्षित कमी नहीं आई।

समग्र प्रवृत्ति का मूल्यांकन:-

समग्र रूप से, उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति गंभीर बनी हुई है। दुर्घटनाओं, मृतकों और घायलों की संख्या में वृद्धि यह संकेत देती है कि वर्तमान उपाय पर्याप्त नहीं हैं। यदि भविष्य में प्रभावी, समन्वित और बहुआयामी रणनीतियाँ नहीं अपनाई गईं, तो स्थिति और विकराल हो सकती है।

राष्ट्रीय तुलना

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभर कर सामने आई हैं, जिनका प्रभाव न केवल मानव जीवन पर बल्कि देश की आर्थिक एवं सामाजिक संरचना पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। राष्ट्रीय स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि मोटरीकरण, शहरीकरण तथा परिवहन अवसंरचना पर बढ़ते दबाव के साथ दुर्घटनाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। इस राष्ट्रीय परिदृश्य में उत्तर प्रदेश का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल तथा सड़क नेटवर्क की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राष्ट्रीय तुलना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सड़क दुर्घटना रिपोर्टों के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लाखों सड़क दुर्घटनाएँ दर्ज की जाती हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा राज्यों से संबंधित होता है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रमुख हैं। यद्यपि कुछ राज्यों में दुर्घटनाओं की कुल संख्या अधिक दिखाई देती है, किंतु उत्तर प्रदेश की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी अधिक पाई जाती है। यह तथ्य इस ओर संकेत करता है कि राज्य में दुर्घटनाएँ अपेक्षाकृत अधिक घातक स्वरूप ले लेती हैं।

जिलावार विश्लेषण

उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की समस्या को गहराई से समझने के लिए जिलावार विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। राज्य के विभिन्न जिलों की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या घनत्व, आर्थिक गतिविधियाँ, सड़क नेटवर्क, यातायात प्रवाह और प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक भिन्नता पाई जाती है। राज्य-स्तर पर प्रस्तुत समग्र आँकड़े केवल समस्या की व्यापकता को दर्शाते हैं, जबकि जिलावार अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सड़क दुर्घटनाएँ समान

रूप से वितरित नहीं हैं। कुछ जिलों में दुर्घटनाओं की तीव्रता अत्यधिक है, जबकि कुछ जिलों में यह अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। यह असमानता सड़क सुरक्षा नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मध्य, पूर्वी और बुंदेलखंड अंचलों में सड़क दुर्घटनाओं का स्वरूप स्पष्ट रूप से भिन्न है:

- **पश्चिमी उत्तर प्रदेश:** गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर जैसे जिले औद्योगिकरण, तीव्र शहरीकरण और राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे की अधिकता के कारण दुर्घटनाओं के दृष्टिकोण से संवेदनशील पाए गए हैं। भारी वाहन और निजी वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण यातायात घनत्व बढ़ता है और दुर्घटनाओं की संभावना अधिक होती है। दिल्ली-एनसीआर से निकटता के कारण दैनिक आवागमन भी दुर्घटनाओं की संख्या को बढ़ाता है।
- **मध्य उत्तर प्रदेश:** लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव और बाराबंकी जिले प्रशासनिक, औद्योगिक और शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। शहरी यातायात, सार्वजनिक परिवहन, ई-रिक्शा, ऑटो-रिक्शा और दोपहिया वाहनों की अधिकता दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ाती है। लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में ओवर-स्पीडिंग और यातायात नियमों का उल्लंघन मुख्य कारण हैं।
- **पूर्वी उत्तर प्रदेश:** प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ और बलिया जिले धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र होने के साथ ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। इन जिलों में दुर्घटनाओं की कुल संख्या कुछ शहरी जिलों की तुलना में कम होती है, लेकिन मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। इसका कारण खराब सड़क अवसंरचना, संकरी सड़कें, प्रकाश व्यवस्था की कमी, यातायात संकेतकों का अभाव और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा की कमी है।
- **बुंदेलखंड क्षेत्र:** झांसी, बांदा, चित्रकूट और महोबा जिले संख्या की दृष्टि से कम दुर्घटनाओं वाले हैं, परंतु मृत्यु-दुर्घटना अनुपात अधिक है। खराब सड़कें, लंबी दूरी पर स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता और आपातकालीन सेवाओं की देरी दुर्घटनाओं को घातक बनाती हैं।

तालिका 2: उत्तर प्रदेश के चयनित जिलों में सड़क दुर्घटनाएँ, मृतक एवं घायल (पिछले पाँच वर्षों का औसत, काल्पनिक आंकड़े)

जिला	दुर्घटनाएँ (औसत)	मृतक (औसत)	घायल (औसत)
गाजियाबाद	4,500	350	5,200
लखनऊ	5,200	420	6,000
कानपुर नगर	4,800	390	5,600
प्रयागराज	3,200	310	3,900
वाराणसी	3,100	305	3,850

झांसी	1,800	280	2,100
-------	-------	-----	-------

तालिका से स्पष्ट होता है कि शहरी और औद्योगिक जिलों में दुर्घटनाओं और घायलों की संख्या अधिक है। बुंदेलखंड एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाओं की संख्या कम होने के बावजूद मृत्यु अनुपात अधिक है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारों से जुड़े जिलों में दुर्घटनाओं की आवृत्ति अधिक है। उदाहरण के लिए, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़े जिले गंभीर दुर्घटनाओं के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं।

जिलावार मृत्यु-दुर्घटना अनुपात

उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव को समझने के लिए मृत्युदर और दुर्घटना की संख्या का अनुपात (मृत्यु-दुर्घटना अनुपात) महत्वपूर्ण मापदंड है। यह अनुपात यह दर्शाता है कि किसी जिले में होने वाली दुर्घटनाएँ कितनी घातक हैं। जिलावार विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण और पिछड़े जिलों में मृत्यु-दुर्घटना अनुपात शहरी जिलों की तुलना में अधिक है, जो सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता को उजागर करता है।

जिलावार आँकड़ों का विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि कुछ जिले सड़क दुर्घटनाओं के “हॉट-स्पॉट” के रूप में उभर रहे हैं। इन जिलों में ओवर-स्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाना, हेलमेट और सीट-बेल्ट का उपयोग न करना तथा यातायात नियमों की अनदेखी प्रमुख कारण हैं। ग्रामीण जिलों में सड़क की खराब स्थिति, गड्ढे, अतिक्रमण, पशुओं की आवाजाही और अपर्याप्त संकेतक दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं। इसके अलावा, घायलों को समय पर अस्पताल न पहुँचाया जाना मृत्यु दर को बढ़ाता है।

तालिका 3: जिलावार मृत्यु-दुर्घटना अनुपात (काल्पनिक डेटा)

जिला	दुर्घटनाएँ (औसत)	मृतक (औसत)	मृत्यु-दुर्घटना अनुपात (%)
गाजियाबाद	4,500	350	7.8
प्रयागराज	3,200	310	9.7
झांसी	1,800	280	15.6

ग्रामीण एवं पिछड़े जिलों (जैसे झांसी) में मृत्यु-दुर्घटना अनुपात शहरी जिलों की तुलना में अधिक है। यह असमानता सड़क सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं में अंतर को दर्शाती है।

शहरी बनाम ग्रामीण जिलों में तुलनात्मक स्थिति

उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की समस्या शहरी और ग्रामीण जिलों में भिन्न रूप लेती है। शहरी जिलों में दुर्घटनाओं की संख्या अधिक होती है, जबकि ग्रामीण जिलों में मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। यह

दर्शाता है कि राज्य-स्तरीय एक समान नीति पर्याप्त नहीं है और प्रत्येक जिले की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार रणनीति अपनाना आवश्यक है।

तालिका 4: शहरी बनाम ग्रामीण जिलों में सड़क दुर्घटनाओं की तुलनात्मक स्थिति (काल्पनिक डेटा)

क्षेत्र	दुर्घटनाएँ (औसत)	मृतक (औसत)	घायल (औसत)
शहरी जिले	5,000	400	6,000
ग्रामीण जिले	2,800	350	3,200

शहरी जिलों में कुल दुर्घटनाएँ अधिक हैं, पर मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम है। ग्रामीण जिलों में कुल दुर्घटनाएँ कम होने के बावजूद मृत्यु-दुर्घटना अनुपात अधिक है। यह संकेत देता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा और सड़क अवसंरचना में सुधार की आवश्यकता अधिक है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं का सर्वेक्षण यह स्पष्ट करता है कि यह एक बहुआयामी और गंभीर सामाजिक समस्या है, जो समय के साथ और अधिक जटिल होती जा रही है। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि शहरी जिलों में दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है, जबकि ग्रामीण और पिछड़े जिलों में मृत्यु-दुर्घटना अनुपात उच्च है। प्रमुख कारणों में ओवर-स्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाना, हेलमेट और सीट-बेल्ट का न उपयोग, सड़क अवसंरचना की कमी और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की अपर्याप्तता शामिल हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से, दुर्घटनाओं के परिणाम न केवल प्रभावित व्यक्तियों बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी लंबे समय तक आर्थिक, शारीरिक और मानसिक प्रभाव डालते हैं। अध्ययन यह भी संकेत देता है कि राज्य-स्तरीय समान नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं; हर जिले की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार **स्थानीय और लक्षित रणनीतियों** की आवश्यकता है। सड़क सुरक्षा उपायों में सुधार, कड़े नियम प्रवर्तन, यातायात अवसंरचना का आधुनिकीकरण और त्वरित आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करना दुर्घटनाओं और उनकी गंभीरता को कम करने के लिए अनिवार्य हैं। अंततः यह अध्ययन नीति निर्माताओं, प्रशासन और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए मूल्यवान दिशा-निर्देश प्रस्तुत करता है, ताकि उत्तर प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं की दर में स्थायी कमी लाई जा सके और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

संदर्भ

1. भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), भारत में सड़क दुर्घटनाएँ - 2023, नई दिल्ली।
2. भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), भारत में सड़क दुर्घटनाएँ - 2022, नई दिल्ली।
3. भारत सरकार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएँ 2023, नई दिल्ली।

4. उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2025, लखनऊ।
5. उत्तर प्रदेश सरकार, सड़क सुरक्षा डैशबोर्ड - दुर्घटना विश्लेषण 2025, लखनऊ।
6. भारत सरकार, एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (iRAD), MoRTH, नई दिल्ली।
7. भारत सरकार, ई-विस्तृत दुर्घटना रिकॉर्ड (ईडीएआर), एमओआरटीएच, नई दिल्ली।
8. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), सड़क सुरक्षा 2022 पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट, डब्ल्यूएचओ, जिनेवा।
9. भारत सरकार, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति, विश्विद्यालय मंत्रालय, नई दिल्ली, 2010।
10. भारत सरकार, मोटर वाहन अधिनियम, (संशोधित संस्करण)।
11. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा दिशानिर्देश, एनएचएआई, भारत।
12. भारत सरकार, सेफ ड्राइव सेव लाइफ अभियान, एमओआरटीएच।
13. पेडेन, एम., स्कर्फील्ड, आर., स्लीट, डी., एट अल., सड़क यातायात चोट निवारण पर विश्व रिपोर्ट, डब्ल्यूएचओ/विश्व बैंक, 2004।
14. UN, सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई के दशक की वैश्विक योजना 2011–2020, संयुक्त राष्ट्र।
15. UN, सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक 2021–2030, संयुक्त राष्ट्र।
16. भल्ला, के. एट अल., भारत में सड़क यातायात चोटें: सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ का अनुमान लगाना”, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंजरी कंट्रोल एंड सेफ्टी प्रमोशन।